

been taken by Government is more than Rs. 4 crores.

श्री बलराज मधोक : अध्यक्ष महोदय मैं अभी खेमकरन से होकर आया हूँ और वहाँ पर आपने जो कुछ काम किया है उसको देखा है। यह काम केवल शहरी मकानों तक ही सीमित है जबकि मुख्य रूप से एपीकल्चरल इलाका है और पाकिस्तान की सीमा तक जितनी भूमि है वह बहुत उपजाऊ है और उस खाी भूमि को ज़र काश्त लाने के लिए आवश्यकता है कि उन लोगों को, जोकि वहाँ पर काम करते हैं, कुछ परमानेंट बैनिफिट्स दिये जायें, कुछ टैक्स बैनिफिट्स और कुछ डेवलपमेंट करने के लिए। इस मामले में एक्कार्टमेंट ने कुछ काम किया है, कुछ ट्रैक्टमेंट भेजे हैं जोकि काम कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार की ओर से इस मामले में क्या उनको परमानेंट बैनिफिट्स देने की कोई स्कीम है ताकि पाकिस्तान की सीमा तक हमारी एक इंच भूमि भी बिना काश्त के नरहे, सारी जमीन काश्त में आ जाये ?

SHRI D. R. CHAVAN: It is only about a month back that I paid a visit to Khem Karan, not only to Khem Karan but to the border also. I may state for the information of the House that upto the border not even an inch of land has been left over by these persons and that they are cultivating all the land. I have seen it actually. Concerning special benefits, I do not understand what special benefits are to be given.

श्री प्रेम चन्द बर्मा : अध्यक्ष महोदय स्टेटमेंट के पेज 1 पर और पेज 4 पर दो बातें हैं। ए० पर 80 लाख रुपये का खर्च बताया है। मैं जानना चाहता हूँ इस मिलसिल में कि खेमकरन, बरकी और डेरा बाबा नानक पर अलग अलग कितना खर्च हुआ है ? यह मैं इसलिये जानना चाहता हूँ क्योंकि एक ओर के लोग कहते हैं कि उससे हमें फायदा नहीं हुआ है, दूसरी ओर के लोगों को अधिक फायदा हुआ है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि उन्होंने कहा है कि एक्स प्रेशिया ग्रान्ट सेंशन करते हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो ग्रान्ट सेंशन की है उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कितना किया है ? इस मिलसिले में जहाँ तक मेरी इत्तला है वह एक्स प्रेशिया ग्रान्ट पूरी तकसीम नहीं हुई है और वह खया पड़ा हुआ है इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ।

SHRI D. R. CHAVAN: As regards the distribution and disbursement of ex-gratia grants, I had a meeting with the Rehabilitation Minister there in Amritsar and, concerning that, practically 99 per cent of the schemes which are grant schemes have been implemented. Concerning the break-up of the figures of expenditure as to how much has been spent in Burki and how much has been spent in other areas, that break-up is not there. But more than Rs. 4 crores have been spent.

#### सिद्धियों का पुनर्गठन

\*1054 श्री बलराज मधोक : क्या संसद-हार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिपक्षी नेताओं ने विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित संसद् की अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियों के पुनर्गठन, उनकी गतिविधियों के क्षेत्र को विस्तृत बनाने तथा उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के बारे में, सरकार को कुछ सुझाव दिये हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो वे सुझाव क्या हैं और उन पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

संसद-हार्य तथासंचार मंत्री (डा० राम सुभद्र सिंह) : (क) और (ख) प्रतिपक्षी नेताओं से विभिन्न मंत्रालयों की अनौपचारिक सलाहकार समितियों के पुनर्गठन

के लिये निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुए थे :—

(I) इन समितियों के प्रतिवेदन, जिन में समितियों द्वारा लिये गये निर्णय और निष्कर्ष हों, समय-समय पर सभा पटल पर रखे जाने चाहिए ;

(II) इन समितियों के सभापति गैर-सरकारी सदस्य (कांग्रेस दल तथा विरोधी दल दोनों लगभग समान संख्या में) होने चाहिए ; तथा

(III) कुछ विभागों के लिए विशेष प्रबन्ध किया जाना चाहिये। रक्षा, वाणिज्य, औद्योगिक विकास तथा ममदाय कार्य और निर्माण आवास तथा पूति मंत्रालयों के लिए स्थायी समितियां या संसदीय समितियां, गठन की जानी चाहियें और उन्हें जब आवश्यक हो, गवाहों को बुलाने अथवा सरकारी कर्मियों के मंगाने का अधिकार होना चाहिये।

इन सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए अनीप-चारिक सलाहकार समितियों के कार्य चालन में कुछ सुधार किये गये हैं और एक वर्ष की अवधि समाप्ति के पश्चात् इनके कार्य चालन का पुनर्विलोकन किया जायगा।

**श्री बलराज मधोक :** अध्यक्ष महोदय श्री मंत्री महोदय ने बताया कि कुछ सुझाव दिये गये थे, उन सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया, केवल यह कहा गया है कि जो कमेटियां हैं उन के कार्यक्रम में, उनके काम के ढंग में कुछ सुधार किया गया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वे क्या सुधार किये गये हैं ?

**डा० राम सुभग सिंह :** सुधार यह किया गया, है जिसकी इत्तला प्रतिपक्षी नेताओं को दे दी गई है, कि अगर किसी कमिटी में यह धीम विचार हो कि एक खास

निर्णय लिया जाय और उसको क्रियान्वित करने का निर्णय हो लेकिन अगर किसी कारणवश मंत्रालय उसे क्रियान्वित करने में असमर्थ हो तो उसकी इत्तला उस कमिटी को दे दी जायेगी अथवा फिर उसे क्रियान्वित ही किया जायेगा। दूसरे कि कार्यवाही को प्रचालित करने के लिए उसे जरूर सदस्य के पास भेजा जायेगा।

**श्री बलराज मधोक :** हमारी संसद में 520 सदस्य लोकसभा के और करीब 250 सदस्य राज्य सभा के हैं। इतने बड़े देश की सारी बातें यहाँ पर डिस्कम नहीं हो पाती हैं इसलिए संसद की कार्यवाही ठीक ढंग से चलाने के लिए और जो सदस्य हैं वे ठीक ढंग से अपने सुझाव दे सकें, इस के लिए आवश्यक है कि ये कमेटियां हों और इसी आधार पर इन समितियों का गठन भी किया गया था लेकिन जिस प्रकार में आज यह कमेटियां हैं वे कोई यूजफुल पर्यज सब नहीं करती (व्य-धान) तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो सुझा दिया गया है कि इनको स्टैंडिंग कमिटीज का रूप दिया जाय जैसा कि यू० एस० ए० में है या और मुल्कों में है, उस में क्या आपत्ति है ? कि सुझा नहीं माना गया है, अपोजीशन पार्टीज के मैम्बर्स इन कमेटियों का वायफाट बन रहे रहे हैं ?

**डा० राम सुभग सिंह :** यू० एस० ए० की जो चर्चा की गई कि जिस प्रकार से वहाँ पर कमेटियां हैं, उसी प्रकार उसे यहाँ भी कमेटियां हों तो जो वहाँ पर व्यवस्था है उससे यहाँ पर भिन्न व्यवस्था है, युनाइटेड स्टेट्स में मजिस्ट्रल कांग्रेस के प्रति दायित्व नहीं रखता परन्तु यहाँ के मजिस्ट्रल मंडल का मीधा दायित्व लोक सभा के प्रति है। (व्य-धान) दोनों की विधियां अलग अलग हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके पूर्वाधिकारी श्री माकलकर

जी के समक्ष यह बात रखी गई थी और डा० राधाकृष्णन् के समक्ष भी रखी गई थी उन्होंने इस की बात ... (व्यवधान) ...  
 "जू के यूनाइटेड स्टेट्स की चर्चा की गई थी इसलिए मैं यह बता रहा था। तो उस को मछे नजर रखते हुए यहां परतव्शीली आई । और उन में सुधार करने की बात में से पहले बताई क्योंकि सत्र को एक साथ चलाने का काम हम लंग ही करते हैं । हमारी यह इच्छा नहीं है कि किरा की उपेक्षा की जाय ।

श्री बलराज मधोक : भाई दूसरा प्रश्न जिसमें मैंने कहा था कि विरोधी पक्ष बाजों ने इन अनीपक्षिक परामर्शदात्री समितियों का बायकाट कर रखा है और उन से त्यागपत्र दे रहे हैं उसका उत्तर मंत्री महोदय ने नहीं दिया है ।

डा० राम सुभग सिंह : कुछ त्यागपत्र अवश्य मिले हैं वैसे मैं उन त्यागपत्रों की उपेक्षा नहीं करता चाहता लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि इन कमिटियों की मीटिंग्स काफ़ी सफल हुई हैं । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 20 साल से ड्रामा करते आ रहे हैं । यह ड्रामा करने में बड़े हाशियार हैं ।

**SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI:**  
 The hon. Minister may please try to understand the anxiety of the hon. members of this House. I would like to know this from the hon. Minister. Though the immediate reference was not available with me, he referred to it. I remember, this was referred to at the time of Mr. Mavalankar and also Dr. Radhakrishnan. May I know what were their opinions on the subject?

**DR. RAM SUBHAG SINGH:** Dr. Radhakrishnan said:

"In the present context, the case for a Standing Committee seems to be very feeble."

Mr. Mavalankar said:

"In the form of Government in which the executive is wholly responsible to the House, no Ministry can function effectively and with one mind if it has to consult the different sections of the House through Standing Committees in the details of administration."

**SHRI RANGA:** When late Shri Mavalankar and Dr. Radhakrishnan were considering this matter, at that time, 90 per cent of the House was under the control of one Party. Previous to the achievement of freedom, we used to have these committees and at that time we considered all these things it never came in the way of the then administration which was more bureaucratic and which, at the same time, used to receive the Resolutions of those committees. The present position is that, as my hon. friend said, they wanted to give one year's trial. They have given that one year. Last year they started it. Since last year, the correspondence has been going on and the Opposition Parties have been non-cooperating with these committees. Some of the members at that time when they did not know that the Opposition leaders were taking this view, had expressed their wish to be members of those committees, but, thereafter, they informed the Ministries concerned and also my hon. friend their unwillingness to continue to be associated with those committees.

I know personally my hon. friend, Mr. Ram Subhag Singh, is not keen on differing from us, but then he happens to be the Minister now. Earlier both of us were Secretaries—I was the senior Secretary and he was the junior Secretary—of the Congress Party. The Congress Party has had a very good system. They have their

own informal committees to which they invite the Ministers. The Ministers used to be good enough to be present there and try to listen to their views. In addition to that, there used to be these consultative committees to satisfy the opposition parties.

In the light of these things, since that one year which they wanted to give for trial is almost over now and the new year is going to be started, may I know whether they would now try and accede to those suggestions and demands that have been placed before them unanimously by all the Opposition leaders. After all, we have not asked for too much; we have asked for only five committees, out of which three could be presided over by the Congress and two could be presided over by the Opposition. Already they have one Opposition member as the Chairman of one of the three very important Financial Committees. It is not too much out of the way, when there is this Cabinet monopoly of power here, that the Opposition has asked for, and it is only our privilege that we have asked this from the Parliamentary point of view, with your protection, Sir, only to be able to give greater consideration to those various demands, various administrative matters, for which the House is not in a position to give sufficient time. That is why I would urge upon you to use your good offices also not only with this poor Minister but also with the whole Cabinet and see that the Cabinet behaves in a democratic manner and accedes to the demands made by the Opposition leaders.

DR. RAM SUBHAG SINGH: There is no question of our behaving in an undemocratic manner. We are responsive to every idea and we propose to function as democratically as one can conceive of. Therefore, I say that we have now tried for about a year and we propose to consult the leaders of the Opposition, and virtually the entire Parliament; we will also take your guidance, Sir, and come to a decision.

157 (A) LS—2.

श्री शिव नारायण : इस सरकार की विरोधी दलों के प्रति कितनी उदारता है इसका प्रमाण इस बात से साफ़ मिल जाता है कि सबसे बड़ी कमेटी जिसका कि नाम पब्लिक एकाऊन्ट्स कमेटी है उसके चेयरमैन विरोधी दल के हैं। मैं चाहूंगा कि संसद्-कार्य मंत्री इस हाउस की जो सुप्रीम एगारिटी है अध्यक्ष की तो अध्यक्ष महोदय के प्रीडोसैसर स्वर्गीय श्री मावलंकर ने इस सम्बन्ध में जो रूलिंग दी हुई है उसे मेहरबानी करके पढ़ दें ताकि उन सब को सैटिसफैक्शन हो सके।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमन्, अभी जो पहले प्रश्न किया गया था तो उसके उत्तर में मैंने मावलंकर जो को उस रूलिंग का पहला वाक्य पढ़ा था। दूसरा वाक्य उनका यह है

“The Ministry comes with a definite policy and it is being accepted by the majority of the House. It will not lead to smooth working to have heterogeneous committees, even though they may be advisory, which have to be consulted on almost every matter or act of administration.”

SHRI SURENDRANATH DWIVEDI: It has nothing to do with financial committees. We are concerned with the rights of the House, with the rights of the members of the House. It is not a matter between the Congress and the Opposition. So far as the Informal Consultative Committees are concerned, our experience, not only of the last year but of all these years, is that they are almost useless committees, serving no purpose whatsoever. Therefore, if Parliament has to function through committees, we have suggested that there should be a better and active association of members in scrutinising the activities of the Ministry. For that purpose, Standing Committee for only four Ministries were suggested. It is not that we wanted

Standing Committees for all the Ministries. To begin with, we wanted Standing Committees for four Ministries and Consultative Committees, not Informal Consultative Committees but Parliamentary Committees of consultative nature, for other Ministries. I want to know what prevented the Government from accepting this stand. Let the Congress members not think that it is only the Opposition which is pleading for it. It is for the entire members of the House to be associated like this. Is this not the experience of the Minister? The entire Opposition has boycotted these committees and, therefore, these are merely Congress committees which are known as Informal Consultative Committees. Sometimes the Ministers say that the Consultative Committees have given this advice. Let us stop this altogether.

DR. RAM SUBHAG SINGH: Actually there is no question of any difference of opinion between the Congress and the Opposition in this matter because we all want to function in an effective manner. It is not true that these committees, which came into being in 1954 and which have been functioning since then have functioned uselessly, because they have contributed a lot.

Regarding the constitution of four Parliamentary Committees in respect of four Ministries, we did consult the concerned Ministries and we also tried to pursue the system that obtains in U.K., and as the House knows, so far, it has not been agreed to constitute Parliamentary Committees, but we are open and we are going to consult these leaders. My esteemed friend, Mr. Surendranath Dwivedy, is also one of the leaders. We will be consulting them very soon.

SHRI G. VISWANATHAN: From the reply of the Minister it seems that he wants to do something but there are legal and Constitutional hurdles in the way.. (Interruptions) May I inform him that in Australia, where the form of Government is the same as ours,

the Parliamentary Committee is given the power to summon even Ambassadors as witnesses? Why can the hon. Minister not gracefully and straightway concede the request of the Opposition?

DR. RAM SUBHAG SINGH: How can I accede to emulating the pattern of Australia gracefully and instantaneously? It shall have to be gone into by the entire House and everybody concerned. For, this system was decided upon by the Constituent Assembly and it has come into practice later with the consent of the Lok Sabha and the Rajya Sabha. So, it shall have to be gone into again.

MR. SPEAKER: Now, Shri Madhu Limaye.

SHRI BEDABRATA BARUA rose—

MR. SPEAKER: It is the demand of the Opposition. Why should the hon. Member get up and take the time of the House? I do not mind calling him, but the hon. Minister is absolutely capable of defending himself.

श्री मधु लिमये : तीन-चार रोज पहले छः सात घंटे की बहस के बाद हम लोगों ने 1015 करोड़ रुपये सुरक्षा के लिये मंजूर किये । सारा देश हंस रहा है और हमारे मतदाता हम से पूछ रहे हैं कि क्या इसी तरह हम सरकारी खर्च पर नियन्त्रण रखते हैं ? 1000 करोड़ से ऊपर की रकम हम छः घंटों में मंजूर कर देते हैं । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि सभी विरोधी दलों ने जिस मांग को उठाया है अगर वह उसको मंजूर करने के लिये तैयार नहीं हैं तो वह और हम मिल कर जनता के पास जायें और जनता इस बारे में फैसला दे । वह खूब इस्तीफा दे कर इस मुद्दे पर चुनाव लड़ें और जनता की राय मांगे ।

MR. SPEAKER: This is not the occasion for that.

**श्री मधु लिमये :** अगर जनता इसके पक्ष में वोट देती है कि डा० राम सुभग सिंह की राय सही है तो ठीक है लेकिन अगर वह हार जाते हैं तो वह स्थायी समितियों की मांग को कबूल करें और इस देश में प्रजातंत्र को जीवित करने का काम करें ।

**डा० राम सुभग सिंह :** मैं इसके लिये तैयार हूँ बशर्ते श्री मधु लिमये दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं से यह स्वीकार करा लें कि यह इतना अहम मसला है जिस पर उनके त्याग-पत्र देने की जरूरत है ।

**श्री मधु लिमये :** इस पर मजाक नहीं करना चाहिये ।

**डा० राम सुभग सिंह :** उनके मस्तिष्क में इतनी उर्वरा शक्ति भरी हुई है कि वह छोटी छोटी बातें ले कर परेशान रहते हैं और बड़ी बात उनकी समझ में आ ही नहीं सकती है ।

**श्री मधु लिमये :** यह छोटी बात नहीं है । आर्क वत को जनता नहीं मानेगी ?

**MR. SPEAKER:** All the Members of the Opposition are agreed on this. There is no difference of opinion among the Members of the Opposition; all of them are united on this; from the first group to the last group all of them are united.

**SHRI NATH PAI:** So are you.

**MR. SPEAKER:** They have been asking for this for the last one year. Government, of course, has to consider it. The hon. Minister has agreed that he will consult the Leaders of the Opposition groups again. Then, let us see a step further and see if we can do anything like that.

**श्री मधु लिमये :** आप जरा ताकत के साथ लोक सभा और प्रजातंत्र की रक्षा कीजिये ।

**श्री रवि राय :** आप पालियामेंट्री कमेटी बना दीजिये ।

**MR. SPEAKER:** I am here always to help . . .

**श्री मधु लिमये :** आप उन पर दबाव डालिये ।

**SHRI S. KANDAPPAN:** You should help us on this.

**MR. SPEAKER:** Now, the Question Hour is over . . .

**SHRI S. M. BANERJEE:** I have been rising, but I have not been allowed. This is a question which has been put which concerns the Members of Parliament as such.

During the conference of the Chief Whips which was held recently at Simla, there was unanimity of views whether on the Congress side or on the Opposition side, that such informal consultative committees should be abolished and there should be standing committees instead. The conference was presided over by the hon. Minister himself. I am not in favour of bye-elections, and I do not want a bye-election immediately on this issue. But I would only submit that if such a unanimous decision of the Chief Whips' Conference is going to be violated like this, then in future we shall think a thousand times before attending such conferences.

**DR. RAM SUBHAG SINGH:** That is not a fact, because the Chief Whips' Conference never said that the consultative committees should be abolished.

**SHRI S. M. BANERJEE:** Informally it was said.

**DR. RAM SUBHAG SINGH:** I am reading out the recommendation, which was as follows:

"The Conference, while appreciating the recent changes made in the working of the informal consultative committees at the Centre with a view to make them more effective recommends that similar com-

mittees may also be set up in all States, Union Territories....'.

So, I do not know wherefrom the hon. Member got that impression.

**SHRI S. M. BANERJEE:** Let him read out the whole thing.

**MR. SPEAKER:** Before going to the short notice question, I would like to say one thing. Yesterday, I had said that Shri Samar Guha and the Education Minister had agreed to something. There is nothing wrong in that. I want that there should be agreement between the Minister and hon. Members. My work would become easy if that type of agreement is there. Therefore, there is nothing wrong in that. If a short notice question can be put and the hon. Minister agrees to answer it, that would be a very good thing. There is nothing wrong in that.

Today also, there is a short notice question in the name of Shri Samar Guha. Let him put it now.

#### SHORT NOTICE QUESTION

##### "Gherao" in Jadavpur University

**S.N.Q. 17. SHRI SAMAR GUHA:** Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recently the Vice-Chancellor, Registrar and 50 Members of the teaching staff of Jadavpur University were "gheraoed" by the students for over a whole day and night;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government to ensure honour, dignity and security of the University teachers of the said University in particular and of the other Universities in general; and

(d) whether Government have any plan to improve the teacher-student relations with a view to tackle the

problems of students' discipline in Universities and other educational institutions?

**THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN):** (a) A section of students of Jadavpur University "gheraoed" the Vice-Chancellor, some teachers and members of the Governing Body on March 19 upto 11-30 p.m. Again on the 30th March, 1968, the Vice-Chancellor, with 46 teachers, officers and office staff, was confined to the Committee Room from 5-30 p.m. on that day to 3 P.M. on the following day,

(b) The students of the Faculty of Engineering and Technology demanded the postponement of University examinations from 10th April to 29th April, 1968.

(c) The matter primarily concerns the State Governments.

(d) The Education Commission has, in its report, recommended setting up of Joint Committees of staff and students for discussion of common problems and difficulties. It has also recommended that efforts may be made to remove educational deficiencies that contribute to students unrest and the setting up of an adequate consultative and administrative machinery to prevent the occurrence of acts of indiscipline. The recommendations of the Education Commission have been forwarded to the State Governments and Universities for consideration and implementation to the extent considered feasible.

**SHRI SAMAR GUHA:** In view of the fact that students' strikes, demonstrations, gheraos and other forms of expressing grievances of the students are almost plaguing the educational life of our country and also creating a lot of trouble for the progress, peace and dignity of our educational institutions, and keeping in view the recommendation made by the Education Commission, will the hon. Minister convene a national convention